

प्रश्नक

आर०डी० पालीवाल
राजिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग 2

देहरादून, दिनांक 31 अगस्त, 2007

विषय : रिट याचिका (एस०बी०) संख्या-402/2004 बी०के० खेवरिया प्रति उत्तरांचल राज्य व एक अन्य में मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2006 के विरुद्ध मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र (Review Application) दायर किया जाना।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक शारान के पत्र संख्या-यूओ 153/XXXVI(1)-बी/2007 दिनांक 08 मार्च, 2007 के सन्दर्भ में अपने पत्र दिनांक 03.05.2007 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- मामले के तथ्य यह है कि श्री बी०के० खेवरिया तदर्थ रूप से प्रोन्नत हैं, उन्होंने नियमित प्रोन्नति हेतु मा० उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन (एस०बी०) संख्या 402/2004 दायर की जिसमें नियमित प्रोन्नति की मांग की। इस याचिका में विभाग की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं किया गया। उक्त याचिका में मा० उच्च न्यायालय के मा० युगल न्यायाधीशगण की खण्ड पीठ ने दिनांक 11.07.2006 को परमादेश जारी किया कि याची को नियमित रूप से प्रोन्नत करने हेतु लोक सेवा आयोग के परामर्श से विभागीय प्रोन्नति समिति (D.P.C.) की बैठक आयोजित की जाय।

3- चूंकि लोक सेवा आयोग के परामर्श से डी०पी०सी० की बैठक, नियमित वयन हेतु ही आयोजित की जाती है और नियमित वयन अभी किया जाता है, जब एक संवर्ग का गठन हो गया हो। उत्तराखण्ड राज्य में अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के संवर्ग का विधिवत गठन नहीं हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य कार्मिकों का अभी अन्तिम बंटवारा नहीं हुआ है, अतः बिना बंटवारा हुए नियमित प्रोन्नति हेतु कार्यवाही नहीं की

जा सकती और न ही नियमित वयन किया जा सकता है। इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए शासन के पत्र दिनांक 08.03.2007 द्वारा आपसे अनुरोध किया था कि मा० उच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र (Review Application) दायर की जाय। परन्तु आपने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र (Review Application) दायर न कर विशेष अपील दायर करने का सुझाव अपने पत्र में दिया है। मा० न्यायालय की युगल न्यायाधीशमण की खण्ड-पीठ के निर्णय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में ही विशेष अपील दायर नहीं की जा सकती है।

4- उक्त अनुरोध है कि कृपया विलम्बमर्बण प्रार्थना पत्र के साथ तुरन्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र (Review Application) प्रस्तुत करें जिसमें मा० न्यायालय को उक्त स्थिति से अवगत कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

(आर०डी० पालीवाल)
सचिव।

संख्या : यू०ओ०^{५५१} / xxxvi(1)एक/2007 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- (1) महाधिवक्ता मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
 - (2) सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मामले से गिद्ध किसी अधिकारी/कर्मचारी को पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र (Review Application) दायर करने हेतु विधि व्यव सहित मुख्य स्थायी अधिवक्ता से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
 - (3) स्टाफ आफीसर, मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - (4) गार्ड बुक/एन०आइ०सी०।

आज्ञा से,

prulakimul
(आर०डी० पालीवाल)
सचिव।